विचार बिन्दु

प्रकृति अपरिमित ज्ञान का भंडार है, पत्ते-पत्ते में शिक्षापूर्ण पाठ हैं, परंतु उससे लाभ उठाने के लिए अनुभव आवश्यक है। –हरिऔध

यूनिफॉर्म पर एक अलग कोण से चंद बातें

हाल में कर्नाटक राज्य में उडुपी के एक कॉलेज में गणवेश (यूनिफ़ॉर्म) को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है वह काफी फैल चुका है, और यह दुर्भाग्य पूर्ण है। उस विवाद के अनेक आयाम हैं और हरेक अपने-अपने नज़रिये से उस पर अपनी बात कह रहा है। यह विवाद शैक्षिक परिसर-व्यवस्था तक सीमित न रहकर राजनीतिक हिसाब-किताब का मामला बन चुका है। इस मामले में दो बातें विशेष रूप से कही जा रही हैं। एक तो यह कि अगर कोई शैक्षिक संस्थान अपने विद्यार्थियों के लिए यूनिफ़ॉर्म निर्धारित करता है तो विद्यार्थियों को अनिवार्यत: उस यूनिफ़ॉर्म में ही संस्थान में आना चाहिए। इसके विपरीत दूसरे पक्ष का कहना यह है कि कोई क्या पहने यह सवाल उसकी अपनी आज़ादी से जुड़ा है और किसी को भी यह हक़ नहीं है कि वह उसे कुछ पहनने या न पहनने के लिए निर्देशित करे। इसी के साथ पर्दा, स्त्री की आज़ादी, अपनी धार्मिक आस्था के अनुरूप जीवन यापन, अल्पसंख्यकों के अधिकार जैसे अनेक मुद्दे भी उभरे हैं। ये सारे मुद्दे अपनी जगह। इन मुद्दों पर खूब चर्चाएं हो ही रही हैं। इन से गुज़रते हुए मेरा ध्यान तो इस बात की तरफ गया कि आखिर यह यूनिफ़ॉर्म है क्या? मेरी तलाश जाकर रुकी ऑक्सफॉर्ड लर्नर्स डिक्शनरी पर, जहां स्कूल यूनिफ़ॉर्म को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। मैं उस परिभाषा का हिंदी अनुवाद दे रहा हूं। डिक्शनरी के अनुसार: *''किसी ख़ास स्कूल में विद्यार्थियों द्वारा पहने जाने वाले ख़ास कपड़े। स्कूल यूनिफ़ॉर्म धारण करना ब्रिटिश परम्परा है और अमरीका में यह बहुत कम चलन में है। अधिकांश स्कूलों में विद्यार्थियों को किसी ख़ास रंग के, प्राय: गहरे नीले, काले अथवा गहरे हरे रंग के कपड़े पहने होते हैं। कुछ स्कूलों और विशेष रूप से प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों को किसी ख़ास दुकान से खरीदे हुए कपड़े ही पहनने होते हैं। स्कूल यूनिफ़ॉर्म में प्राय: लड़कों और लड़कियों दोनों ही को स्कूल के रंगों वाली एक धारीदार टाई भी पहननी होती है। कुछ बहुत ही पारम्परिक स्कूलों जैसे एटन की तरह के पुराने परम्परागत पब्लिक स्कूलों के विद्यार्थियों को 19वीं शताब्दी या उससे भी पहले की शैली के कपड़े पहनने होते हैं।''*

इस बारे में बहुत व्यवस्थित और प्रामाणिक जानकारी तो नहीं मिल सकी है लेकिन मोटे तौर पर यह माना जा सकता है सन 1552 में पहली दफा लंदन के एक चैरिटी स्कूल जिसका नाम क्राइस्ट्स हॉस्पिटल था, में स्कूल यूनिफ़ॉर्म लागू की गई थी। यह स्कूल अनाथ और ग़रीब बच्चों के लिए था। इसके बाद बहुत जल्दी पूरी ब्रिटेन में स्कूल यूनिफ़ॉर्म चलन में आ गई। पहले इसे सामुदायिक स्कूलों ने अपनाया और बाद में अभिजात वर्गीय स्कूलों ने भी इसे अपना लिया। क्योंकि इन स्कूलों में नीले रंग के ब्लेज़र चलन में थे, इन्हेंब्ल्यूकोट स्कूल्सभी कहा जाने लगा था। यहां ब्रिटिश स्कूलों की चर्चा इसलिए भी प्रासंगिक है कि हमने अपनी शिक्षा के लिए ब्रिटिश ढांचे को ही मुख्यत: अपनाया है। वैसे अब आहिस्ता-आहिस्ता अमरीकी स्कूलों में भी यूनिफ़ॉर्म का चलन बढ़ा है और एक अध्ययन के अनुसार लगभग बीस प्रतिशत अमरीकी स्कूलों में यूनिफ़ॉर्म अनिवार्य है।

यूनिफ़ॉर्म की उपादेयता को लेकर जानकार स्पष्ट रूप से दो भागों में बंटे हुए हैं। एक समूह है जिसका मानना है कि यूनिफ़ॉर्म न केवल अनुशासन और स्कूल की पहचान के लिए उपयोगी है, इससे विद्यार्थी का शैक्षिक उन्नयन भी होता है, वहीं दूसरी तरफ वह समूह भी है जो इसे विद्यार्थी की स्वतंत्र अभिव्यक्ति में बाधक मानते हुए इसे ग़ैर ज़रूरी मानता है। इस समूह का सोच यह है कि विद्यार्थी अपनी वेशभूषा से भी स्वयं को अभिव्यक्त करता है और हमें कोई हक़ नहीं है कि हम उसकी इस अभिव्यक्ति को बाधित करें। विद्यार्थी की अभिव्यक्ति की आज़ादी की यह बात बहुत आगे तक गई और सन 1969 में अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय तक को इस बात पर विचार करना पड़ा। उस समय वहां के विद्यार्थी अपनी बांहों पर काली पट्टियां बांध कर वियतनाम युद्ध के मसले पर अपने देश की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। स्कूल ने यूनिफ़ॉर्म का हवाला देते हुए जब इसकी अनुमति नहीं दी तो विद्यार्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय के दरवाज़े पर दस्तक दी, और अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि यूनिफ़ॉर्म का अर्थ यह नहीं है कि विद्यार्थी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को खो दें। इसी तरह इस बात को लेकर भी अनेक अध्ययन हुए हैं कि क्या यूनिफ़ॉर्म के कारण विद्यार्थी के अध्ययन का उन्नयन होता है, और 1998 के एक प्रसिद्ध अध्ययन, जिसे ब्रुंसना एण्ड रॉकमोर का अध्ययन कहा जाता है, ने यह कहा है कि स्कूल यूनिफ़ॉर्म और विद्यार्थी के शैक्षिक उन्नयन के बीच कोई संबंध नहीं है।

महत्व की बात यह है कि विद्यार्थी स्कूल जा सकें, पढ़ सकें। अगर कोई यूनिफ़ॉर्म उसके स्कूल जाने में बाधक बनती है तो हमें उस यूनिफ़ॉर्म के औचित्य पर पुनर्विचार करना चाहिए। वर्तमान विवाद भी अगर इस दिशा में हमारे सोच-विचार का उत्प्रेरक बनता है तो यह शुभ होगा।

बहुत सारे स्कूल अपनी ख़ास पहचान के लिए कोई ख़ास यूनिफ़ॉर्म लागू करते हैं। हम भीड़ में भी यूनिफ़ॉर्म देखकर यह पहचान लेते हैं कि इसे धारण करने वाला अमुक संस्थान का विद्यार्थी है। ज़ाहिर है कि यह उस संस्थान विशेष की ब्राण्डिंग का मामला ज़्यादा होता है। सरकारी स्कूलों में यूनिफ़ॉर्म लागू करने के पीछे एक बड़ा तर्क यह भी दिया जाता है कि उसके कारण विद्यार्थियों में अमीरी-गरीबी के प्रदर्शन पर लगाम लगती है। एक हद तक यह बात सही भी है। यूनिफ़ॉर्म विद्यार्थियों में समानता का भाव जागृत करती है। बहुत सारे स्कूल, विशेष रूप से लड़कियों के स्कूल उनकी फैशन परस्ती पर रोक लगाने के लिए भी यूनिफ़ॉर्म व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। वहां यूनिफ़ॉर्म कपड़ों से आगे जाकर नाखूनों, बालों, आभूषणों, एसेसरीज़ आदि को भी अपने घेरे में ले लेती है।

बावज़ूद यूनिफ़ॉर्म के लाभ और हानियों पर विभाजित राय के, भारत के ज़्यादातर स्कूलों में, अर्थात कक्षा एक से बारह तक यूनिफ़ॉर्म चलन में हैं। इसको लेकर समय-समय पर छोटे-मोटे विवाद भी होते रहते हैं पर कुल मिलाकर यह चलन में है। विद्यार्थी और उनके अभिभावक भी इस स्थिति को स्वीकार कर चुके हैं। विद्यार्थी इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कब वे स्कूली पढ़ाई पूरी कर कॉलेज में पहुंचें ताकि उन्हें यूनिफ़ॉर्म की एकरसता से मुक्ति मिले और वे अपने मन पसन्द कपड़े पहन कर अपने शैक्षिक संस्थानों में जा सकें। हमारे यहां अधिकांश उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में यूनिफ़ॉर्म की कोई बाध्यता नहीं है। अलबत्ता संस्थान अपनी पहचान के लिए बैज या लोगो जैसे अन्य उपकरणों का प्रयोगकर लेते हैं। यहीं यह कहना भी ज़रूरी है कि बहुत सारे शैक्षिक संस्थानों के लिए यूनिफ़ॉर्म उनके व्यवसाय के प्रसार का भी एक माध्यम है। वे एकरूपता के नाम पर किसी एक ख़ास दुकान से, और प्राय: तो अपने ही संस्थान से ड्रेस खरीदने की अनिवार्यता बता कर अपने आर्थिक हितों का संवर्धन करते हैं।

यूनिफ़ॉर्म व्यवस्था को लेकर भारत में देशी-विदेशी का मुद्दा भी कभी-कभार उभरता है। सामान्यत: लड़कों की वेशभूषा पैण्ट कमीज़ वाली और लड़कियों की स्कर्ट शर्ट या सलवार कमीज़ वाली होती है। कुछ लोग इन वेशभूषाओं को भारतीय-विदेशी वाले नज़रिये से देखकर इनसे असहमत होते और इनके विकल्प सुझाते हैं। हमारे अपने राजस्थान में दीक्षांत समारोहों की यूनिफ़ॉर्म में भारतीयता के प्रवेश से हम सब परिचित हैं। सोचिये, अगर स्कूलों की यूनिफ़ॉर्म में भी भारतीयता लागू कर दी जाए तो जनता और ख़ास तौर पर युवा पीढ़ी की प्रतिक्रिया क्या होगी! लड़कियों की वेशभूषा के मामले में स्त्री देह को लेकर हमारा ख़ास सोच प्रबल रहता है, जबकि स्कूल जाने वाली बच्चियां अपने बारे में भिन्न सोच रखती हैं, इस उम्र में वे आत्म प्रदर्शन को लेकर अधिक सजग होती हैं और वे किसी न किसी तरह अपने मन की करने की जुगत भिड़ाती रहती हैं।

हमारे यहां यूनिफ़ॉर्म को लेकर अधिक विचार विमर्श नहीं हुआ है। हमने आम तौर पर इस बात को स्वीकार कर लिया है कि स्कूल होगा तो यूनिफ़ॉर्म भी होगी ही। शेष दुनिया में ऐसा नहीं है। वहां इस मुद्दे पर खुलकर संवाद होता है और यथावश्यकता बदलाव भी होते हैं। मुझे लगता है कि हमारे यहां भी यूनिफ़ॉर्म को पत्थर की लकीर मान लेने की बजाय इस पर खुले मन से विचार होना चाहिए। इसी के साथ यह भी समझा जाना चाहिए कि यूनिफ़ॉर्म विद्यार्थियों के लिए है, विद्यार्थी यूनिफ़ॉर्म के लिए नहीं हैं। एक लचीला रवैया रखा जाना बहुत ज़रूरी है। महत्व की बात यह है कि विद्यार्थी स्कूल जा सके, पढ़ सके। अगर कोई यूनिफ़ॉर्म उसके स्कूल जाने में बाधक बनती है तो हमें उस यूनिफ़ॉर्म के औचित्य पर पुनर्विचार करना चाहिए। वर्तमान विवाद भी अगर इस दिशा में हमारे सोच-विचार का उत्प्रेरक बनता है तो यह शुभ होगा।

अतिथि सम्पादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

कृषि संकट बाजार पर खेतिहरों के नियत्रंण से दूर होगा!

सुचित्रा आर्य

भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है । भारत में खेती-किसानी केवल व्यवसाय मात्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह संस्कृति और सभ्यता है जिसके दायरे में कई धर्म और असंख्य जातियां एवं कई भाषाएं आती हैं । आईडिया ऑफ इंडिया का पोषण और रक्षण करने वाली संस्कृति और सभ्यता खेती-किसानी ही है जिसकी बदौलत भारत को कृषि प्रधान कहा गया है। भारत में प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के दायित्व का निर्वहन जिसमें वृक्ष, नदी पहाड़ पशुधन जीव जंतु की रक्षा की जिम्मेदारी निभाना सम्मलित हैं।

इतने सबके बावजूद किसान को अर्थ नीति में जितना महत्व मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है। भारत की संरचना ऐसी है कि जब तक खेती इस संकट से नहीं निकलेगी किसान खुशहाल नहीं हो सकता । खेत का औसत आकार लगातार घट रहा है तथा हमारी कृषि आबादी प्रत्येक वर्ष लगभग 1.5 प्रतिशत बढ़ रही है, छोटी काश्तकारी की प्रधानता कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आर्थिक किफायत की राह में मुख्य बाधा है। इसके अतिरिक्त छोटे और सींमात किसानों के पास मोलभाव की शक्ति कम है क्योंकि उनके पास बिक्री योग्य अधिशेष कम होता है और किसानों को बाजार की कीमत स्वीकार करनी ही पड़ती है।

खेती की लागत, जोखिम प्रतिफल एवं प्रतिकूलताएं दिनोंदिन बढ ती जा रही हैं जिसके परिणामस्वरूप किसान अधिकाधिक कर्जदार होते जा रहे हैं। आजादी के बाद और उदारीकरण, औधोगीकरण एवं अन्य आर्थिक - समाजिक सुधारों के माध्यम से उद्योगों का कायाक्लप हुआ और उद्योगों को उभारने के लिए करोड़ों रूपये के सरकारी राहत दी जाती रही है लेकिन जब बात कृषि क्षेत्र की आती तो इसका क्रियानवन उतना विवेकपूर्ण तरीके से नहीं हुआ! बड़े पैमाने पर कृषि के लाभ के लिए सहकारिता की परिकल्पना राजस्थान ने तो आजादी के तुरन्त बाद भी की थी लेकिन समय के साथ योजनाएं धीमी पड़ गई जिसके चलते लघु क्षेत्र वाले किसानों की बहुलता आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।

राजस्थान में भूमि का निशुल्क मालिकाना हक काश्त करने वाले किसानों के हक में भूमि नाम कराने वाले पुरोधा चौधरी कुम्भाराम आर्य ने 6 दशक पहले इसकी विधिवत शुरुआत 15 अक्टूबर 1955 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू करके मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में की थी।

उन्नत दर्जे के भू सुधार अधिनियमों की बदौलत राजस्थान देश में सबसे कम भूमिहीन आबादी वाला प्रदेश है एवं प्रतिव्यक्ति/परिवार भूमि का औसत वितरण लगभग सम्मान है लेकिन बाद में इन सुधारों की गति धीमी पड़ गई जिसके फलस्वरूप आज भी किसान अत्यधिक पेचिदिगियों का सामना करते हुए तहसील से लेकर कोर्ट और राजस्व मंडल तक चक्कर लगा रहा है जिसमें उसका श्रम, धन व समय का अपव्यय हो रहा है।

डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बजट 2020 में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राजस्व विभाग के

■ किसान का बाजार पर नियत्रंण नहीं होने से वह शोषित उत्पादक बनकर रह गया है!

कार्यों का डिजिटलाइजेशन किया था, जिससे घर बैठे ही भू-नामान्तरण, गिरादवरी रिपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं परन्तु बीघा-बिस्वा/हैक्टेयर रूपांतरण की कार्यवाही सभी जगह नहीं होने से भी कृषकों को दिक्कतों से गुजरना पड़ता है।

प्रदेश की अन्य कृषि संबंधी समस्याओं में सिंचाई सुविधाओं के निराकरण को लेकर केन्द्रीय जल आयोग में प्रदेश सरकार ने सिंचाई पानी के मुद्दे को उठाया तो है लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं । नहरी क्षेत्र में खाले निर्माण, मुरबाबंदी, किलेबंदी जैसे कार्य लम्बित है। कृषि कनेक्शन सालों साल से अटके पड़े हैं तथा क्लेम के लिए बीमा कम्पिन्यां और बैंक दफ्तरों में काश्तकारों को चक्कर काटने पड़ रहें हैं । इसके अतिरिक्त नकली बीज, उर्वरकों की अनुपल्बधा जैसी समस्याएं तथा केन्द्र और राज्य की सहभागी योजनाओं में सामजंस्य अभाव व अव्यवहारिक नीतियों का कृषकों को समाना करना पड़ता है।

राजस्थान सरकार कृषि बजट को पृथक पेश कर रही है जो कि अच्छी शुरूआत है लेकिन कृषि क्षेत्र को मिलने वाली पर्याप्त बिजली और सिंचाई में सार्वजनिक क्षेत्र के महंगे निवेश जैसे कृषि विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना होगा एवं कृषि उद्योग के आधुनिकरण बाजारीकरण आदि के लिए भी सुधार की आवश्यकता है। किसान बीज खरीदने से लेकर कृषि जिसं बेचने तक कंम्पिनयों पर निर्भर रहता है । कम्पिनयां किसान के लिए परिमार्जित डकैत साबित होती हैं । किसान का बाजार पर अपना नियत्रंण नहीं होने की वजह से वह शोषित उत्पादक बनकर रह गया है! कृषि संकट दूर करने के लिए सरकार को बाजार पर खेतिहरों का नियंत्राण बढाने वाली नीतियों को गढ़ना एवं कृषि कार्ययोजनाओं एवं आपदा प्रबंधन को अतिंम छोर तक पहुंचाने की व्यवस्था को दूरस्थ एवं समयबद्ध करना होगा। उपरोक्त तमाम प्रकार की जटिलताएं खेती के विकास को अवरूद्ध किये हुए हैं इन्हें दूर करने के लिए संस्थागत सुधारों की महती आवश्यक्ता है।

सुचित्रा आर्य
पूर्व विधायक

इस बार के केंद्रीय बजट से क्या गरीबों की संख्या में वृद्धि नहीं होगी?

प्रो. वीर बहादुर सिंह

केंद्रीय बजट में गरीब और उनकी गरीबी पर प्रत्यक्ष रूप से कोई विवरण अथवा संकेत नहीं किया गया है। 1 फरवरी, 2022 को केंद्र सरकार का वार्षिक बजट लोकसभा में वित्त मंत्री मैडम सीतारमण जी ने प्रेषित किया वो मुझे एक रहस्यमय पहेली जैसा मुझे प्रतीत हुआ, दूसरे दिन अखवार में पढ़ने पर बजट के पहलू कुछ स्पष्ट हुए।

सैद्धान्तिक रूप से बजट के विभिन्न आयाम ऐसे होने चाहिए जिन्हें आम शिक्षित व्यक्ति सुगमता से समझ सके बजट के प्रस्तुतीकरण में वर्ष में अर्जित राजस्व/धन व उसके स्त्रोतों का वर्णन होना चाहिए, इनके पश्चात् फिर खर्च करने की प्राथमिकताएं और उन पर कुल व्यय और यदि प्रस्तावित परियोजना एक वर्ष से अधिक समय में पूरी हो रही हो तो उस स्तिथि में वर्तमान में एक वर्ष में उस पर संभावित व्यय को यथोचित दर्शाना उपयुक्त रहता है, इससे राजस्व की प्राप्ति और उसके खर्च का ब्यौरा भलीभांति समझ में आ जाता है। वर्तमान प्रस्तुतीकरण में ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया

ये कहना उचित होगा कि बजट में प्राथमिकताएं और उन पर खर्चे बहुत उचित और दूर दृष्टि से तय किये गए हैं।

नया बजट दूरगामी नतीजे देने वाला है क्योंकि इसमें दीर्घकालीन योजनाओ पर फोकस किया हुआ है, दूसरी तरफ डिजिटल बाजीगरी का भरपूर उपयोग किया गया है इसलिए हर किसी के लिए यह बजट समझना आसान नहीं है। तत्कालिक फायदों को दरकिनार करते हुए भविष्य के भारत की तस्वीर पर फोकस है। डिजिटीलीजेशन और शहरीकरण पर जोर दिया गया है, विकास को गति देने के लिए ढांचागत विकास पर अधिक ध्यान रखा है। उदाहरण के लिए अगले तीन वर्ष में 400 नयी वन्दे मातरम् रेल गाड़ियां शुरू होंगी, वही प्रधान मंत्री आवास के लिए एक साल में 80 लाख मकान बनाने का प्रस्ताव किया है और इसी साल देश में 25 हज़ार किलोमीटर लम्बी सड़कें भी बनायी जावेगी।

क्रिप्टोकोर्रेंसी जो अभी कुछ समय पहले ही चलन में आयी है, उस पर और अन्य वर्चुअल होने वाली क्रियाओं से होने वाली कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स लागू होगा, रिज़र्व बैंक इसी वर्ष डिजिटल करेंसी भी जारी करेगा और 5 जी इंटरनेट सेवा भी शुरू हो जावेगी।

आयकर की दरों में कोई न तो बदलाव किया गया है और न ही इनकम स्लैब में, किसी वर्ग के लिए आयकर में किसी भी प्रकार की कोई छूट दी गयी है। सब पहले जैसा ही है और आयकर पर सब पूर्ववत ही है जैसे निवेश या अन्य कोई छूट। इस बाबत मध्य और लोअर इनकम ग्रुप में घोर निराशा हुयी है। वित्त मंत्री को एक प्रेस रिपोर्टर से वार्तालाप में सुना कि महंगाई बढ़ने पर निचले और मध्यम वर्ग के लोग क्या अपना जीवनयापन संतोष प्रद रख पाएंगे? जबकि उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान बजट में नहीं किया है जिससे वे आने वाली कष्टप्रद महादशा से निपट पाएं। वित्त मंत्री का उत्तर चौंकाने वाला था। जब उन्होंने ये कहा कि महंगाई तो सभी देशो में बढ़ रही है । एक अर्थ शास्त्री की दृष्टि से महोदया के कथन पर सभी को सोचना चाहिए। महंगाई जब बढ़ती है उस समय मध्यम वर्ग, जो निम्न आय वर्ग से ठीक ऊपर होता है वह निचली श्रेणी में आ जाता है और इस प्रकार गरीबों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है।

प्रधान मंत्री इंदिरा गाँधी के समय 'गरीबी हटाओ' नारा बढे जोर-शोर से दिया गया मगर तत्कालीन सरकार के किसी प्रवक्ता ने कहा 'ये कब कहा गया कि गरीब नहीं रहेंगे? गरीब हटाने की तो कोई बात नहीं की गयी, वे तो रहेंगे। अर्थात गरीबी हटाते हुए गरीब कम नहीं होंगे, वे तो रहेंगे'। उत्तर सुनकर अचम्भा तो हुआ ही, सरकार की बुद्धिमत्ता से मन भी प्रसन्न हो गया।

■ वर्तमान बजट से गरीबी बढ़ना क्या पार्टी इन पावर के लिए सुखदाई होगा?

■ एक रिसर्च एजेंसी के अनुसार भारत में गरीब लोगों की संख्या13.4 करोड़ हो चुकी है

वर्तमान बजट के रहते यदि गरीबों की संख्या बढ़ती है जो अवश्यभावी है तो वह स्तिथि क्या पार्टी इन पावर के लिए सुखदाई नहीं मानी जाएगी? क्योंकि गरीब और गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर करने वाले लोगों के लिए सरकार ने अनेक लगभग मुफ्त और बिलकुल मुफ्त सुविधाएँ दे रखी हैं, अत: कितने भी लोग गरीब वर्ग में बढ़ जाये वे सब सरकारी मिलने वाली मुफ्त की योजनाओं का लाभ सुगमता से उठा सकेंगे और सरकार का गुणगान करेंगे और चुनाव के समय उस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में अपना वोट भी डालेगा। एक रिसर्च एजेंसी की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत अभी भी एक लोअर-मिडिल इनकम देश है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में गरीब लोगों की संख्या 134 मिलियन (13.4 करोड़) हो चुकी है जो व्यापार और उद्योग में मंदी (रिसेशन) के समय केवल 5.9 करोड़ थी, अर्थात दोगुनी से भी अधिक वृद्धि गरीबों की संख्या में हो गई। रिपोर्ट आगे कहती है कि भारत में एक गरीब 2 डॉलर (145 रूपये लगभग) प्रतिदिन या उससे कम पर जीवन निर्वाह करता है, फिर क्या ऐसी स्थिति वर्तमान बजट के उपरांत नहीं आ सकती?

केवल उपरोक्त वर्णित आयाम को छोड़कर बजट किसानो के लिए निर्धारित समर्थन मूल्य देने के लिए कही अधिक सजग है और उसी के अनुसार प्रावधान भी बढाकर रखा है। देश की दो नदिओं के आलावा तीन और नदिओं को जोड़ने की योजना, रक्षा बजट में संतोषजनक बृद्धि आदि अनेकों प्रस्ताव बजट में उल्लेखित हैं, जिनसे दूरगामी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, तथा रक्षा मसलों पर कही अधिक मजबूती दिखाई देगी।

आधारभूत सुबिधाओं के अतिरिक्त इस बजट से कितना लाभ देश की जनता को मिलेगा, वर्ष उपरांत आंकलन पर ही पता चल पायेगा?

प्रो. वीर बहादुर सिंह,
पूर्व कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

रेल प्रशासन बेपरवाह, आमजन को रेलयात्रा पड़ रही महंगी

फुलेरा, (निसं)। रेलनगरी के नाम से विख्यात फुलेरा रेलवे स्टेशन से हजारों की संख्या में लोग प्रतिदिन रेलयात्रा करते हैं, परन्तु रेल प्रशासन की उदासीनता के चलते अधिकांश ट्रेनों में आरक्षण करवाकर ही रेलयात्रा सम्भव हो पा रही है। जिससे आमजन को आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है । गौरतलब है कि फुलेरा से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग जयपुर-अजमेर व मकराना की ओर रेलयात्रा करते हैं। रेल प्रशासन की ओर से सामान्य टिकट की सुविधा शुरू हो जाए तो लोगों को आरक्षण के लिए लगने वाले अतिरिक्त भाड़ से मुक्ति मिल जाये।

फुलेरा से जयपुर यात्रा करने के लिए एकतरफा किराया एक्सप्रेस ट्रेन में 50 रूपये तथा सुपरफास्ट ट्रेन में 65 रूपये लगता है, इस प्रकार दोनों तरफ का कुल किराया क्रमश 100 व 130 रूपये प्रतिदिन वहन करना पड़ता है, जो कि दिहाड़ी मजदूरी अथवा अन्य निजी नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं हो पा रहा है। जबकि सामान्य टिकट फुलेरा से जयपुर का 35 रूपये का है। दैनिक रेलयात्रा करने वाले लोगों को रेल विभाग की ओर से मासिक सीजन टिकट 270 रूपये का बनाया जाता था, जिससे उन्हें एमएसटी बनवाने में समस्या भी नहीं होती थी और आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ता।

■ फुलेरा-जयपुर के मध्य संचालित 36 ट्रेनों में से मात्र 5 में ही एम. एस. टी. व सामान्य टिकट से यात्रा संभव

फुलेरा जक्शंन रेलवे स्टेशन पर जयपुर की ओर जाने वाली लगभग 36 ट्रेन है परन्तु रेलवे प्रशासन की ओर से मात्र 5 रेलगाड़ियों में ही सामान्य टिकट की सुविधा दी जा रही है। दैनिक रेलयात्री संघ एकीकृत के अध्यक्ष अशोक वासदेव ने बताया कि रेलनगरी फुलेरा जंक्शन से अन्यन्त्र स्थान पर दैनिक रेलयात्रा करने वालों की संख्या लगभग 15-17 हजार है। जिसमें से करीब 10 हजार व्यक्ति फुलेरा से जयपुर की ओर रेलयात्रा करते थे, जबकि अन्य लोग किशनगढ, अजमेर, नांवा, कुचामन व मकराना की ओर यात्रा करने वालों की संख्या भी लगभग 6-7 हजार व्यक्ति प्रतिदिन की रहती थी।

इन 15-17 हजार लोगो में से अधिकांश लोग दिहाडी मजदूर अथवा खुली मजदूरी करने वालों की रहती थी। इसके अलावा भी अन्य स्थानीय लोग भी रेलयात्रा करते हैं। अशोक वासदेव ने बताया कि फुलेरा से जयपुर की ओर रेलयात्रा करने वाले लोगों को सुबह चलने वाली हनुमानगढ़ एक्सप्रेस, ग्वालियर इन्टरसिटी, न्यू भुज-बरेली एक्सप्रेस, रतलाम एक्सप्रेस, जोधपुर इन्टरसिटी व शालीमार एक्सप्रेस में सामान्य टिकट व एमएसटी शुरू करने की नितांत आवश्यकता है। रेल प्रशासन की ओर से शटल, डीएमयू, बीकानेर इंटरसिटी, उदयपुर-जयपुर इंटरसिटी में ही सामान्य टिकट व एमएसटी सुविधा दी गई है। फुलेरा से जयपुर जाने वाले दैनिक यात्रियों के लिए दैनिक रेलयात्री संघ एकीकृत व फुलेरा से अजमेर जाने वाले दैनिक रेलयात्रियों के लिए दैनिक रेलयात्री संगठन बना हुआ। इन सभी के पदाधिकारियों की ओर से हरसंम्भव प्रयास किये जा रहे हैं कि जिससे शीघ्र ही रेल प्रशासन की और दैनिक रेलयात्रियों व अन्य यात्रियों की सुविधा को देखते हुए सामान्य टिकट व मासिक सीजन टिकट बनाया जाये । इसके अतिरिक्त स्थानीय विधायक निर्मल कुमावत, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सांसद कर्नल राज्यवर्धनसिंह राठौड़, केन्द्रीय रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव को भी पत्र लिखा गया है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 14 फरवरी, 2022

माघ मास शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2078, पुनर्वसु नक्षत्र दिन 11:53 तक, आयुष्मान योग रात्रि 9:48 तक, कौलव करण प्रात: 7:25 तक, चन्द्रमा कर्क राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-धनु, बुध-मकर, गुरू-कुम्भ, शुक्र-धनु, शनि-मकर, राहु-वृष, केतु-वृश्चिक राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग दिन 11:53 से सूर्योदय तक है। रवियोग दिन 11:53 से आरम्भ होगा। आज सोम प्रदोष व्रत, विश्वकर्मा जयन्ती, कल्पादि है और गुरू गोरक्षनाथ और मुनि धर्मनाथ जयन्ती है। आज सेन्ट वेलेन्टाइन दिवस है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से 8:32 तक, शुभ 9:55 से 11:18 तक, चर 2:04 से 3:27 तक, लाभ-अमृत 3:27 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 7:08, सूर्यास्त 6:14

मेष
परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

वृष
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिचितों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

मिथुन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। शुभ कार्य के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है।

कर्क
परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी।

सिंह
आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा। मन में असंतोष बना रहेगा। व्यावसायिक मामलों में दुविधा बनी रहेगी।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

वृश्चिक
व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता सफल रहेगी। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। परिवार में संदेश प्राप्त होंगे।

धनु
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

मकर
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

कुंभ
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

मीन
व्यावसायिक कार्य के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।